जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 121 दिनांक:04-09-2024 बुधवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला और बाल विधेयक को 3 सितंबर को ध्वनि मत से पारित कर दिया। जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ''ऐतिहासिक'' कहा।

भारतीय महिला पैरा एथलीट दीप्ति जीवांजी ने महिला 400 मीटर टी20 वर्ग में कांस्य पदक जीता। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकेंड का समय लिया और उनका रिएक्शन टाइम 0.164 सेकेंड रहा। इस तरह दीप्ति तीसरे स्थान पर रहीं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास

अब बंगाल में बलात्कारी को 10 दिन में फांसी

कोलकाता(ईएमएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार के ममता सरकार में कानून मंत्री मोलॉय घटक ने एंटी रेप बिल पास कर दिया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है। अब बंगाल में रेप के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करनी होगी। इस बिल को पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद से ही डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद ही ममता सरकार एंटी रेप बिल लाई है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 पर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दुष्कर्म पीडिता, उसके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूं। यह ऐतिहासिक विधेयक है। विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा देना है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के प्रावधानों के तहत हम जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए एक विशेष अपराजिता टास्क फोर्स का गठन करेंगे। जिससे तय समय में महिला-बाल अपराधों के मामले में जांच पूरी कर दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा

बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से उनकी सरकार ने पीडितों और उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिश की है। साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करने में सक्षम नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने अपराजिता महिला-बाल विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए अन्य राज्यों के लिए भी इस विधेयक को आदर्श बताया। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीएम ने कहा कि क्या होगा अगर मैं भी उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं, जिन कारणों से आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।

यूपी- गुजरात में ज्यादा होते हैं महिला अपराध

ममता बनर्जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर असामान्य रूप से अधिक है, जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताडित महिलाओं को अदालतों में न्याय मिल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के कानून बीएनएस बनाते समय बंगाल से परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद वह इस पर चर्चा चाहते थे। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे राज्यपाल से बिना देरी किए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।

आईसी 814 विवादः केंद्र के साथ बैठक के बाद नेटफ्लिक्स बदलाव को तैयार

नई दिल्ली,(ईएमएस)। वेब सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' को लेकर बवाल के बाद नेटफ्लिक्स इसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। इस सीरीज़ में आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे जाने को लेकर विवाद है। सीरीज़ के भारी विरोध के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को समन जारी कर बुलाया था। मंगलवार को नेटफ्लिक्स हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय के अधिकारियों के सामने पेश हुईं।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मोनिका की बैठक में बातचीत हुई। इस दौरान केंद्र सरकार को नेटफ्लिक्स की ओर से कहा गया कि वेब सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' के आपत्तिजनक हिस्से में बदलाव करने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि भविष्य में नेटफ्लिक्स पर जो भी फिल्में या वेब सीरीज़ आएंगी, उसे देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

इस मामले पर केंद्र सरकार ने कहा है कि क्रिएटिविटी के नाम पर भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। सरकार का कहना है कि हम सपोर्ट करने के साथ कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर्स को आगे भी बढ़ा रहे हैं लेकिन फैक्ट्स के साछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। फिल्म या सीरीज़ को रिलीज़ करने से पहले सही रीसर्च करनी चाहिए और फैक्ट चेक भी होना चाहिए।

'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। इस सीरीज़ को 29 अगस्त को नेटफ्लिक्ट पर रिलीज़ की गई। सीरीज़ में 6 एपिसोड हैं. ये 1999 में हुए कंधार प्लेन हाईजैक की घटना पर आधारित है। विवाद है, इस सीरीज़ के दो हाईजैकरों के नाम पर। इस प्लेन को पांच हाईजैकरों ने हाईजैक किया था. इन आतंकियों ने हाईजैकिंग के दौरान अपने कोड नेम रखे थे। इनके नाम थे, भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। विवाद के बाद सरकार ने नेटफ्लिक्स हेड को तलब किया और अब इसमें ओटीटी प्लैटफॉर्म बदलाव के लिए तैयार हो गया है।

सेबी की चीफ के साथ जुड़ा आई सी आई सी आई बैंक का नाम, शेयरों में आई गिरावट

बैंक ने दी सफाई, माधबी बुच को सिर्फ रिटायरमेंट के लाभ दिए गए

नई दिल्ली,(ईएमएस)। आईसीआईसीआई बैंक ने कांग्रेस द्वारा मार्केट रेग्युलेटर सेबी की चीफ माधबी पुरी बुच पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। बैंक ने इसको लेकर दो टूक कहा कि सेबी चेयरपर्सन के रिटायर होने के बाद उनके सेवानिवृत्ति लाभों के अलावा किसी भी तरह का कोई वेतन या ईएसओपी नहीं दिया गया है। बता दें कि बुच को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने दावा किया था कि सेबी चीफ एक साथ तीन जगहों आईसीआई सीआई बैंक, आईसीआई सीआई प्रुडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थीं। इस विवाद का असर आईसी आईसी आई बैंक शेयर पर दिखा है ये मंगलवार को गिरावट के साथ लाल निशान पर खुला। कांग्रेस के आरोपों के बाद इन पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए आईसी आईसीआई बैंक ने कहा है कि आईसी आईसीआई बैंक या इसकी अन्य ईकाई ने माधबी पुरी बुच को उनके रिटायरमेंट के बाद सिर्फ रिटायरमेंट लाभ दिए हैं। इसके अलावा कोई सैलरी या कोई ईएसओपी का लाभ नहीं दिया है।

बैंक के स्टेटमेंट में कहा गया कि यह ध्यान देने वाली बात है कि सेबी चीफ ने बैंक से 31 अक्टूबर, 2013 से रिटायरमेंट का विकल्प चुना था। ग्रुप के साथ अपने रोजगार के दौरान उन्हें बैंक की तय नीतियों के मुताबिक ही सैलरी, बोनस, ईएसओपी और रिटायरमेंट बेनेफिट्स मिला था जबकि रिटायरमेंट के बाद कोई अलग से बेनेफिट नहीं दिया गया। बीते दिनों अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही माधबी बुच कांग्रेस के निशाने पर आ गई।

कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सेबी चीफ को लेकर कई दावे किए थे। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है लेकिन खिलाड़ी कौन है, इस पर हम निर्णायक तौर पर नहीं पहुंचे हैं। अलग-अलग मोहरे हैं. उनमें से एक मोहरा जिनका नाम है माधबी पुरी बुच। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा था कि सेबी चीफ माधबी को 2017 और 2024 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16.8 करोड़ रुपए की नियमित आय प्राप्त हुई। उन्होंने सवाल किया कि अगर आप पूर्णकालिक सेबी सदस्य हैं, तो आप आईसीआईसीआई बैंक से वेतन क्यों ले रही थीं। यही नहीं ईएसओपी और इसका टीडीएस भी आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थीं। इन्हें लेकर बैंक ने स्टेटमेंट जारी कर स्थिति साफ की है।

सेबी चीफ पर आरोपों में आईसीआईसीआई बैंक का नाम शामिल किए जाने और इस पर बैंक के स्पष्टीकरण का असर आज इस बैंकिंग स्टॉक पर देखने को मिला है। बीते कारोबारी दिन जब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए गए थे, तब आईसीआईसीआई बैंक शेयर मामूली गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। 1239 रुपए पर ओपन होने के बाद ये शेयर स्टॉक बाजार में कारोबार खत्म होने पर 1229.05 रुपए पर बंद हुआ। वहीं मंगलवार को भी इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ये शेयर टूटकर 1227.20 रुपए पर खुला और कुछ ही मिनटों में 122.05 रुपए तक टूट गया।

केजरीवाल की हिरासत 11 तक बढ़ी

नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ गई है। मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 27 अगस्त को केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई।

तेलंगाना-आंध्र में बारिश-बाढ़ से 33 की मौत

23 राज्यों में आज बारिश की संभावना, गुजरात में रेड अलर्ट

नई दिल्ली(ईएमएस)। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। हुदहुद और तितली साइक्लोन की तुलना में पिछले तीन दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं।

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सूरत और भरूच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है।

हिमाचल में वित्तीय संकट.....वेतन और पेंशन नहीं मिला कर्मचारियों को

शिमला (ईएमएस)। भले ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के गहराते वित्तीय संकट के बारे में चिंताओं को दूर करने की कोशिश की हो, लेकिन सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में देरी ने इस आंशका को सच साबित कर दिया। जब सोमवार को उनके बैंक खातों में कोई भुगतान नहीं किया गया। आम तौर पर वेतन और पेंशन हर माह की पहली तारीख को उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। हालाँकि, रविवार होने के कारण वेतन सोमवार को वितरित किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिससे दो लाख से अधिक नियमित कर्मचारी काफी चिंतित हैं।

अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कि वेतन कब वितरित होगा, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के साथ-साथ नौकरशाही के बीच भी चिंता है कि गंभीर वित्तीय संकट के बीच स्थिति से कैसे निपटा जाए। हालांकि पिछले शासनकाल में इसतरह के उदाहरण आए हैं जब राजकोष घाटे में चला गया, लेकिन वेतन और पेंशन में कभी देरी नहीं हुई। हालाँकि, इस बार देरी एक दिनचर्या बन सकती है क्योंकि अधिक ऋण जुटाने का कोई प्रावधान नहीं है और राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर है। विडंबना यह है कि एचपी राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनभोगी, जिन्हें अतीत में हमेशा देरी से वेतन मिलता था, भुगतान प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे।

सीएम सुक्खू ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है, जिसका दोष उन्होंने उनके द्वारा शुरू की गई मुफ्त की संस्कृति को दिया है। राज्य विधानसभा में सुक्खू कहना चाहते थे कि इन सभी मुफ्त सुविधाओं ने उस वित्तीय संकट में प्रमुख भूमिका निभाई है जिसका राज्य वर्तमान में सामना कर रहा है। लेकिन उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा कि राज्य के खजाने की स्थिति जल्द ही बेहतरी के लिए बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र राज्य और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं।

कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि हर बार पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख तक वेतन मिल जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं जब 3 सितंबर है और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है।

संदीप घोष को कोर्ट से झटका

-आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा

कोलकाता,(ईएमएस)। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद जांच के दायरे में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने डॉ घोष को 8 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

यहां बता दें कि सीबीआई ने अदालत से डॉ घोष की 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिनों की सीबीआई हिरासत मंजूर की है। वहीं, अदालत ने इसी मामले में गिरफ्तार चल रहे एक अन्य आरोपी अफसर अली खान की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए ट्रेनी महिला डॉक्टर रेप व मर्डर मामले में जांच शुरू करते हुए अनेक लोगों से पूछताछ की थी। इनमें मेडीकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। इसे लेकर सीबीआई कई दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को सोमवार को हिरासत में ले लिया था। वैसे डॉ घोष की यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर की गई है। आज अदालत में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने 10 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 08 दिन सीबीआई हिरासत की इजाजत दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने यह कार्रवाई 15 दिनों से अधिक की पूछताछ पूर्ण करने के बाद की है। इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतों को हिदायत पीठ के फैसलों के खिलाफ काम ना करे

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इंकार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि इस तरह की समयावधि निर्धारित करना असाधारण मामलों में ही तय किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों के जल्दी निपटान और जल्द सुनवाई के लिए जमानत देने से इंकार शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसलों के खिलाफ है।

रिपोर्ट मुताबिक, पीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ की घोषणा के बावजूद, हमने देखा है कि कई उच्च न्यायालय जमानत खारिज करते समय मुकदमों की जल्दी सुनवाई तय करे हैं। ऐसा नहीं हो सकता और सिर्फ इस आधार पर जमानत से इंकार करे कि मुकदमे का निपटारा शीघ्रता से होगा। मुकदमे की सुनवाई की सीमा का ऐसा निर्धारण केवल बहुत ही असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि फरवरी में न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि अदालतों को किसी अन्य अदालत में लंबित मामलों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने से बचना चाहिए।

पीएम मोदी का ब्रुनेई दौरा, सुल्तान हसनल से करेंगे मुलाकात

सिंगापुर पीएम के निमंत्रण पर दो दिवसीय दौरे पर कल जाएंगे मोदी

नई दिल्ली, (ईएमएस)। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई दौरे पर रवाना हो गए। यह दौरा एक दिन का होगा। इसके बाद वह बुधवार को सिंगापुर के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का ब्रुनेई और सिंगापुर का ये तीन दिवसीय दौरा अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी, सुल्तान हसनल बोल्कैया के निमंत्रण पर ब्रुनेई गए हैं। वह भारत के पहले पीएम होंगे, जो ब्रुनेई का दौरा करेंगे। इस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा-अगले दो दिन ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहूंगा। इन देशों में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान ध्यान इन देशों के साथ भारत के संबंधों को और गहरा करने पर होगा। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी, सुल्तान हाजी हसनल से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। सिंगापुर में वह राष्ट्रपति थर्मन शणमुगरत्नम, पीएम लॉरेन्स वॉन्ग, वरिष्ठ मंत्री ली सेन लुंग और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मिलेंगे। हम कई प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने को लेकर उत्सुक हैं।

पीएम मोदी के इस दौरे में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के साथ अंतरिक्ष और रक्षा सेक्टर में सहयोग को भी बढ़ाएंगे। ब्रुनेई के साथ भारत पहले ही अंतरिक्ष सेक्टर में कई अहम समझौते कर चुका है। इसके साथ ही इस दौरे से दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी संबंध मजबूत होंगे। इस दौरे पर सेमीकंडक्टर और हाइड्रोकार्बन आयात पर फोकस होने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में कुछ समझौते भी हो सकते हैं। ब्रुनेई को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से काफी अहम देश माना जाता है।

पीएम मोदी 4 सितंबर को सिंगापुर के दो दिनों के दौरे पर रवाना होंगे। यह पीएम मोदी का सिंगापुर का पांचवां दौरा होगा। वह पीएम लॉरेंस वॉन्ग के निमंत्रण पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स से उनकी मुलाकात इस दौरे का अहम बिंदु है।

अजय रात्रा टीम इंडिया के सिलेक्टर बने

नई दिल्ली (ईएमएस)। अजय रात्रा टीम इंडिया के सिलेक्टर बन गए हैं। बीसीसीआई ने रात्रा को भारत की पुरुष चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया है। वह सलिल अंकोला की जगह लेंगे। रात्रा, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर भारतीय टीम का सिलेक्शन करेंगे। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रात्रा का इंटनरेशनल करियर 18 मैचों में ही खत्म हो गया था। उन्होंने साल 2002 में 6 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमशः 163 और 90 रन बनाए। हालांकि, रात्रा को घरेलू क्रिकेट का काफी अनुभव है। उन्होंने हरियाणा के लिए 99 प्रथम श्रेणी मैचों में 4029 रन जुटाए और 240 से अधिक शिकार किए।

बीसीसीआई ने बयान में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीईसी) ने अजय रात्रा को अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष चयन समिति का नया सदस्य नियुक्त किया। रात्रा समिति में सलिल अंकोला की जगह लेंगे।

42 वर्षीय रात्रा को असम, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य कोच के रूप में काम करने का अनुभव है। वह 2023 में दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज सीरीज के दौरान भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सा थे। पिछले साल अगरकर को चीफ सिलेक्टर नियुक्त किए जाने के बाद चयन पैनल में पश्चिम क्षेत्र से दो चयनकर्ता थे। अंकोला पहले से ही समिति का हिस्सा थे।

सुरक्षाबलों ने 9 नक्सली मार गिराए

-दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर रुक-रुक कर फायरिंग जारी; मारे गए नक्सलियों के शव, हथियार-विस्फोटक बरामद

जगदलपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। इलाके में सुबह करीब 10.30 बजे से जवानों और नक्सलियों के बीच रुक-रुककर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बैलाडीला के जंगल में हुई।

जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। नक्सलियों के पास से एसएलआर राइफल, 303 और 315 बोर राइफल, विस्फोटक बरामद हुआ है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने की है।

नक्सलियों की सूचना पर रात में रवाना हुए थे जवान

बैलाडीला की पहाड़ियों के नीचे पुरंगेल, लोहा गांव की तरफ पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को रात में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। जवान जब नक्सलियों के कोर इलाके में घुसे तो नक्सलियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।

राहुल गांधी ने राय मांगी; हुड्डा 3-4 सीटों पर राजी, चंडीगढ़ में इसी फॉमूले से निगम-लोकसभा जीते

हरियाणा चुनाव में कांग्रेस-आप में हो सकता है गठबंधन

पानीपत(ईएमएस)। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई कि वह इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस-आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती लेकिन आप कुरूक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लडऩे पर कांग्रेस-आप ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने नेताओं से पूछा कि क्या हमें हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए?। वहां राय जानने की कोशिश के बाद सीनियर नेता को कहा कि वह नेताओं से बात करे। गठबंधन संभव है या नहीं और अगर हुआ तो इसके फायदे-नुकसान क्या होंगे, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है।

अपनाया जाएगा लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला

माना जा रहा है कि गठबंधन हुआ तो सीट बंटवारे को लेकर लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला ही अपनाया जा सकता है। इसको लेकर आज शाम को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी मीटिंग में स्थिति साफ हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा गठबंधन हो सकता है। इसके लिए आप और बाकी इंडिया के सहयोगी बाकी दलों के साथ बातचीत चल रही है। हम हरियाणा में वोटों का ध्रुवीकरण और भाजपा को रोकना चाहते हैं। वहीं इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो आप को केवल 3-4 सीटें दे सकते हैं। मगर, आप इससे ज्यादा मांग रही है, इसलिए गठबंधन मुश्किल है। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को पता लग गया है कि वह हरियाणा नहीं जीत सकती। इसलिए आखिरी वक्त में कुछ उपाय कर रही है। आप से गठबंधन की बात कर रही है लेकिन प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। कांग्रेस जो मर्जी कर ले, किसी से गठबंधन कर ले, भाजपा ही आएगी।

भाजपा को हराना प्राथमिकता

वहीं आप के संजय सिंह ने कहा कि भाजपा और उसकी नफरत की राजनीति तथा लोगों, किसानों और युवाओं के खिलाफ राजनीति को हराना हम सभी की प्राथमिकता है। हालांकि, सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक रुख आप के हरियाणा मामलों के प्रभारी संदीप पाठक और प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता द्वारा तय किया जाएगा। आप के वरिष्ठ नेता ने कहा, इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय केजरीवाल की मंजूरी के बाद हरियाणा में संगठनात्मक और चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े हमारे नेताओं द्वारा लिया जाएगा।

क्या कर्नाटक में जाएगी सिद्धारमैया की सीएम कुर्सी

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्नाटक में क्या मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, यह ऐसा सवाल है जो कांग्रेस सरकार के गठन के साथ ही कर्नाटक के सियासी गलियारों में चर्चाओं में है। एक बार फिर से इस सवाल पर खूब चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लेकर विपक्ष कई बड़े और गंभीर आरोप लगा रहा है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह पार्टी आलाकमान और विधायकों के फैसले का पालन करुंगा। सीएम ने अपने गृहनगर मैसूरु में यह बात कही।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त देकर कहा कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? इस संबंध में पार्टी विधायक और आलाकमान को फैसला करना हैं, वे जो भी निर्णय लेते हैं, उसका पालन करुंगा। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि इतने लंबे समय के बाद वह कैसे तरोताजा दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी दावा कर रही थी कि वह मुद्दा मामले के मद्देनजर सुस्त दिख रहे हैं, तब सिद्धारमैया ने हंसते हुए कहा, विपक्ष ने इस मामले में झूठ बोला है। अगर उनका झूठ साबित नहीं हुआ है, यह उनके लिए मुश्किल होने वाला है। मैंने झूठ नहीं बोला है, न ही गलत बयान जारी किया है और न ही कोई गलती की है। कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायिक आयोग की कोविड पर एक रिपोर्ट को कथित तौर पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने के सवाल पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इस संबंध में सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट गुरुवार को कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने दावा किया है कि इस रिपोर्ट का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

एटलस साइकल्स के पूर्व प्रेसिडेंट सलिल कपूर ने गोली मारकर आत्महत्या की

नई दिल्ली (ईएमएस)। एटलस साइकल्स के पूर्व प्रेसिडेंट सलिल कपूर ने मंगलवार को दिल्ली स्थित अपने निवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने आर्थिक बोझ का जिक्र करते हुए कुछ लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कपूर का शव दोपहर करीब 1 बजे उनके मैनेजर ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित उनके घर के पूजा कक्ष के पास खून से लथपथ पाया। अधिकारी के अनुसार, कपूर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने सिर में गोली मारी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कपूर के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं, जो कि उनसे अलग रहते हैं। तीन मंजिला इमारत में कपूर अपने मैनेजर और उसके परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि कपूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फॉरेंसिक और क्राइम टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने मौके से सबूत इकट्ठा किए।

बता दें कि कपूर को साल 2015 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। उन पर धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। जनवरी 2020 में उनकी भाभी नताशा कपूर ने भी इसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।

गोगामेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत

नरवाना(ईएमए

जन हितैषी

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीमकोर्ट का ढीला-ढाला रवैया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में बुलडोजर के माध्यम से आरोपियों की संपत्ति को बिना किसी सुनवाई के नष्ट किए जाने पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथन और न्यायाधीश बी आर गवई की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है। उसके बाद भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। उसके अपराध के लिए जो सजा कानून में निर्धारित है, वही सजा उसे दी जा सकती है। आरोपी के अपराध की सजा उसके बच्चों या परिवार जनों को कैसे दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का, यह कहना कि कानून का उल्लंघन होने पर अवैध निर्माण को गिराया गया है। तुषार मेहता का कहना था, जब निर्माण कार्यों में कानून का उल्लंघन हुआ है, तभी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह कहते हुए बुलडोजर एक्शन का बचाव किया। अनधिकृत निर्माण को हटाया गया है। जो कानून संवत है, अवैध निर्माण हटाने से किसी अपराधी को अपराध की सजा नहीं दी गई है। अपराध के मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय द्वारा जो सजा दी जाएगी, वह अपराधी पर लागू होगी। यह कहकर उन्होंने बुलडोजर एक्शन का बचाव किया। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, वह अवैध निर्माण के संरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए देश में एक तरह के दिशा-निर्देश देने पर विचार कर रहे हैं। अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर से न्याय करने की बात खुद मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का अपराध एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा किए जाने पर तत्काल जिला प्रशासन के अधिकारी आरोपी की संपत्ति को अवैध निर्माण बताकर तोड़ देते हैं। इस कार्यवाही से एक समुदाय विशेष के लोगों में आतंक फैलाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। अब वह भाजपा शासित राज्यों से होते हुए अन्य राज्यों में पहुंचने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से यह कहा जा रहा है। अवैध निर्माण होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही की है, वह न्याय संगत है। जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, यह न्याय पालिका के संज्ञान में भी है। मीडिया में भी बुलडोजर के माध्यम से सरकार द्वारा तत्काल न्याय करने की बात कही जा रही है। यह भी न्यायपालिका के संज्ञान में है। उसके बाद भी यदि उस राज्य की हाईकोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट मौन धारण करके रखती है। याचिका दायर होने के बाद भी कई महीनों तक उस पर सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद यही कहा जा सकता है, नियम और कानून सरकारों एवं प्रशासकीय अधिकारियों पर नहीं होते हैं। नियम कायदे कानून केवल आम जनता के लिए हैं। सरकार जो भी काम करती है। वह नियम से ही करती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में न्याय पालिका की जरूरत भी नहीं होगी। यह बात अभी दबे छुपे तरीके से कही जा रही है। जिस तरह से न्यायपालिका का संरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल रहा है। उसके बाद आम आदमी को न्याय मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भीड़ तंत्र द्वारा जिस तरह से तत्काल न्याय किया जा रहा है। सरकारों और न्यायपालिका की चुप्पी के हजारों मामले देखने को मिल रहे हैं। न्यायपालिका की एक तरह से मोन सहमति माना जा सकता है। भारतीय न्यायपालिका का नया रूप है। पिछले 70 वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने स्वयं संज्ञान लेकर इस तरह के मामलों में नागरिकों के मौलिक अधिकार समय-समय पर संरक्षित किए थे। आपातकाल को मानव अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका विरोध पिछले 50 वर्षों से किया जा रहा है। आपातकाल कुछ महीनो के लिए विशेष प्रावधान के तहत लगाया गया था। सँसद ने इसकी स्वीकृति दी थी। समय के साथ आपातकाल के प्रावधान भी समाप्त हो गये। अघोषित आपातकाल के इस दौर में न्यायपालिका की चुप्पी लोगों को आश्चर्य चकित कर रही है। ऐसे ही न्यायपालिका सरकार के दबाव में रही, सरकार की इच्छा और अनिच्छा को ध्यान में रखकर न्याय देने का काम न्यायपालिका करेगी, तो नागरिकों का न्यायपालिका और भारतीय संविधान से मोह भंग होना तय है। पिछले वर्षों में जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के नाम से एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उनकी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। यह सब भय, दहशत और आतंक का वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। उसके बाद भी यदि न्यायपालिका चुप रहती है, तो यही माना जा सकता है कि कानून के नाम पर सरकार और प्रशासन आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से सुनवाई हो रही है, उसमें सरकार और प्रशासन के जिन लोगों द्वारा इस तरह की अवैध कार्रवाई की गई है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त रहेगा। जिन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। बुलडोजर एक्शन पर जिन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यदि उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराकर दंडित किया जाएगा। तभी लोगों का न्यायपालिका के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। सरकार और प्रशासकीय अधिकारी न्यायपालिका और आम नागरिकों के अधिकार, बुलडोजर संस्कृति और तत्काल न्याय के नाम पर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि कठोर कार्यवाही के निर्देश देता है, तभी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लग सकती है।

भागवत कथा- संघ की सक्रियता बढ़ने के मायने..?

भारत की आजादी के बाद से अब तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कई विवादस्पद दौरों से गुजरा है, जिसके तहत् इस संगठन को प्रतिबंधात्मक दायरे से भी गुजरना पड़ा है। खैर, वह सब कांग्रेसी शासन कालों के दौरान हुआ, किंतु आज जबकि पिछले एक दशक से केन्द्र में संघ समर्थक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संघ का दबी जुबान आरोप है कि संघ को सताने की स्पद्र्धा में मोदी सरकार ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है और इस त्रासदी का मुख्य आधार प्रधानमंत्री व उनकी अपनी टोली द्वारा संघ की उपेक्षा है, अपनी इस त्रासदी का जिक्र करने के लिए केरल में संघ ने अपनी तीन दिवसीय समन्वय बैठक बुलाई जिसमें सभी उपस्थिततों को संघ प्रमुख की बातों पर गौर कर निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन भाजपा संगठन के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने अचानक वहां पहुंच कर, ''मीडिया मैनेंज'' कर अपनी आवाज को बुलंदगी के साथ पेश किया और बैचारे संघ प्रमुख की आवाज के साथ उनके प्रयासों पर पानी फैर दिया।

संघ की पिछले कुछ दिनों की भूमिका को देखकर प्रधानमंत्री व उनके सहयोगी सतर्क हो गए थे और उन्होंने इसी रणनीति के तहत् भाजपाध्यक्ष को संघ की केरल बैठक में भेजकर यह सब किया। वर्ना संघ के इस सम्मेलन के पहले दिन जो संघ प्रमुख ने तेवर दिखाए थे, वे ही तेवर यदि तीनों दिन पूरे सम्मेलन में जारी रहते तो वह भाजपा सत्ता व संगठन के लिए ठीक संकेत नही होते, इसीलिए मीडिया को मैनेज कर भाजपा प्रमुख की बात को जोर-शोर से उठाया गया और संघ प्रमुख की बातों को दबा दिया गया।

देश में अब तक कायम हुई भाजपा या पूर्व जनता पार्टी की सरकारों में यह पहली बार हो रहा है, जब संघ अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहा है, इससे पूर्व अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी अटल-अड़वानी ने संघ को प्रमुख माना था तथा ये नेता समय-समय पर संघ पदाधिकारियों से सलाह-मशवरा करते रहते थे, किंतु अब संघ को शायद भाजपा सरकार के चलते पहली बार उपेक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए अब वह जमाना लद गया, जब सत्ता प्रमुख संगठन प्रमुख से मिलने या मशवरे के लिए जाया करता था, आज तो स्थिति यह है कि संघ प्रमुख प्रधानमंत्री से भेंट का समय मांगते है और वह भी कई दिनों तक नही मिल पाता, इसीलिए अब संघ ने भी दबी जुबान मोदी व उनकी सरकार पर सख्त टिप्पणियां शुरू कर दी है। संघ ही नही अब तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दबी जुबान यह कहने में कोताही नही बरतते कि मोदी जी अब बहुत बदल गए है, अब वे 2014 वाले मोदी जी नही रहे और इसी मसले को लेकर सत्तारूढ़ दल व उसके जनक संगठन (संघ) में अच्छी-खासी चर्चा है, जो मोदी जी के चैथे कार्यकाल के लिए शुभ नही मानी जा रही, संघ-भाजपा तथा उसके संगी-साथी मोदी जी के उन तैवरों को ''तानाशाही की झलक'' बता रहे है, यह स्थिति भाजपा में सिर्फ केन्द्र तक ही सीमित नही है, बल्कि भाजपा शासित राज्यों के सत्ता संगठनों में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है। इस स्थिति को लेकर भाजपा के हितचिंतकों व सहयोगियों में भी अच्छी खासी चिंता है व इस स्थिति में भविष्य को लेकर बैचेनी है।

इस प्रकार भाजपाध्यक्ष ने संघ के केरल सम्मेलन में पहुंच कर चाहे संघ का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया हो, किंतु अब जब यह गुस्सा देश के जिलों व तहसील स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तब नड्डा जी कहां-कहां अपनी सफाई पेश करने जायेगें?

(लेखक-ओमप्रकाश मेहता/ ईएमएस)

वर्षा जल को बर्बाद होने से बचाएं

मानसून का महीना हर किसी को आत्मिक आनंद से सराबोर करने वाला होता है इस समय नील व्योम काली घटाओं के केन्द से बंद मेघो के माध्यम से वसुधा को अपनी असमी स्वर्णिम जलबूंदो से तरबतर करने को उत्साहित व आतुर दिखाई पड़ता है। शीतलता भरी छुअन घुल जाने से प्राणी जगत को भीषण गर्मी से राहत मिलने लगती है।

भले शहर में मिटटी के लोग बारिश में भीग जाने से कतराते हो, लेकिन गांव में तो आज भी बारिश को एक उत्सव व त्योहार के रूप में मनाने व बिंदास होकर खूब भीग जाने की परम्परा जीवित है। यहां तो बारिश के आगाज के साथ ही नग्गे बदन बच्चो की टोलियां में धमा चौकड़ी मचाती हुई देखी जा सकती है। हम मानसून की मस्ती में इतने भी मशगूल नही हो जाए कि वर्षा जल संचयन को ही भूल जाऐ। हाल के वर्षो मे वर्षा जल संचयन को लेकर व्यक्तिगत प्रयासो में कमी आई है। पहले गांवो में वर्षा जल संचयन परंपरा का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। दुनिया के सर्वाधिक बारिश होने वाले क्षेत्रो में भारत भी है, यहां हर वर्ष बर्फ पिघलने ओर वर्षा जल के रूप में औसतन 4000 अरब घनमीटर पानी प्राप्त होता है, जबकि यह देश वर्षा जल का 1869 अरब घनमीटर (मतलब सिर्फ 46 प्रतिशत) पानी का उपयोग कर पाता है, बाकी 54 प्रतिशत पानी व्यर्थ में बहकर नदी-नालो के द्वारा समुद्र में चला जाता है। मणिपुर से भी छोटे इजराइल जैसे देशो में जहां वर्षा का औसत 25 से.मी. से भी कम है, वहां भी जीवन चल रहा है।

वहां जल प्रबंधन तकनीक अति विकसित होकर जल की कमी का आभास नही होने देती, अपितु कृषि से कई बहूमूल्य उत्पादो का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। बारिश के पानी का विभिन्न स्त्रोतो व प्रकल्पों व सुरक्षित व संग्रहित रखना व करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल संचयन वर्षा जल के भंडारण को संदर्भित करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर बाद में इसका उपयोग किया जा सके। इस तरह व्यपाक जलराशि को एकत्रित करके पानी की किल्लत को कम किया जा सकता है।

भारत में पेयजल संकट एक प्रमुख समस्या है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा ह और इस वजह से पीने के पानी की किल्लत बढ रही है सिकुडती हरित पटटी इसका मुख्य कारण है। पेड़ों से जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा हासिल होती है वही यही पेड़ भूमिगत जल का स्तर बनाये रखने में भी अहम् भूमिका निभाते है। लेकिन दुत गति से होने वाले विकास कार्यो ने हमारी हरित पटटी की तेजी से बलि ली है उसी का नतीजा है कि न सिर्फ भूमिगत जल का स्तर नीचे गया है, बल्कि वर्षा में भी लगातर कमी आई है। गौरतलब है कि भारत में दो सौ साल पहले लगभग 21 लाख सात हजार तालाब थे। साथ ही लाखो कुंऐ, बावड़ियां झीलें पोखर और झरने भी हमारे देश की गोदी में हजारो नदियां खेलती थी, किन्तु आज से नदिया हजारो में से केवल सैकड़ो में ही बची है। ये सब नदिया कहां गई कोई नही बता सकता है।

जिस भारत में 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा हो यहां आज स्वच्छ जल का उपलब्ध न हो पाना विकट समस्या है। आज देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे है। करीब दो लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते है। नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंन्धन सूचकांक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जिसमें कहा गया है सन 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जायेगी। जिसका मतलब है कि करोड़ों लोगो के लिए पानी का गंभीर संकट पैदा हो जायेगा और देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जायेगी। वर्षा जल संचयन के लिए वर्तमान में कई वैज्ञानिक व परंपरागत विधिया प्रयोग में लायी जा रही है। यहां कुछ ऐसी ही विधियों व प्रणाली का उल्लेख किया जा रहा है, जो वर्षा जल संग्रह में सहायता कर सकती है।

यह वर्षा जल संग्रहण की सबसे उत्तम व आसान विधि है। इस विधि से संचित पानी को किसी अन्य माध्यम से स्वच्छ किये बिना ही इसका मानवहित में उपयोग किया जा सकता है। बांध परियोजनाओं का सफल निर्माण बारिश के जल को संग्रहित करने में काफी कारगर सबित हो सकता है। बांध जैसे प्रकल्पों में जलराशि को लंबं समय तक बांधकर इसका उपयोग नहरों के माध्यम से सिंचाई के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। अगर अब भी हम सचेत नही हुए तो दक्षिण अफ्रीकी शहर केपटाउन की तरह भारत को भी पानी सपने में ही देखने को नसीब होगा हालाकि पूरे विश्व में धरती का लगभग तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, किन्तु इसमें से 97 प्रतिशत पानी खारा है जो पीने योग्य नही है, पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3 प्रतिशत है। इसमें भी 2 प्रतिशत पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1 प्रतिशत पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मानव का दायित्व बनता है कि वो अपने हिस्सा का पानी पहले से ही संग्रहित करके रखे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात के कुछ इलाको ने पारंपरिक रूप से घर के अन्दर भूमिगत टैंक बनाकर जल संग्रह करने का प्रचलन है, इस परम्परा को अन्य राज्यों में लागू कर हम इस गंभीरता को कम कर सकते है। कठोर कानून के द्वारा नदियों में छोडे जाने वाले अपशिष्ट पर लगाम लगाकर जल प्रदूषण को रोका जा सकता है और वर्षा चक्र को बाधित होने से बचाया जा सकता है।

(लेखक- विष्णु अग्रवाल / ईएमएस)(स्वतंत्र पत्रकार)

ऐसा ना हो इधर मूंछ पर ताव दें, उधर अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाए...

(कहो तो कह दूं)

आजकल पता नहीं कौन-कौन सी नई-नई चीजें दुनिया में आ रही हैं। एक खबर पता लगी है कि निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने स्माइल पे नाम का एक फेशियल पेमेंट सिस्टम लागू किया है इसमें ग्राहक को ना तो कैश की जरूरत है, ना कार्ड की, ना मोबाइल की । वह सिर्फ मुस्कुराएगा और पेमेंट हो जाएगा अब आप ही बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसकी जेब से नोट जा रहे हो और वो मुस्कुराए, अपने ख्याल से तो ऐसा इंसान मिलना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है , क्योंकि पैसा जब आता है तब इंसान मुस्कुराता है लेकिन जब पैसा जेब से निकलता है तो मुस्कुराहट ऐसी गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग।और सही बात भी तो है भले ही कार्ड की जरूरत ना पड़ रही हो, मोबाइल की आवश्यकता ना हो, लेकिन माल तो अपने अकाउंट से ही डेबिट हो रहा है ना, अब जब अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा हो तो मुस्कुराने की इसमें बात कौन सी है इसमें एक पंगा और भी है कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि वे लाख मुस्कुराने की कोशिश करलें लेकिन उनके चेहरे का तनाव कम नहीं होता ऐसी स्थिति में भले ही वे कितना ही मुस्कुराने की कोशिश करेंगे लेकिन क्यू आर कोड उनकी मुस्कुराहट को पकड़ नहीं पाएगा और जब तक मुस्कुराहट को पकड़ नहीं पाएगा तब तक पेमेंट होगा नहीं। कई ऐसे भी होते हैं कि उनका चेहरा हमेशा ऐसा लगता है जैसे वे मुस्कुरा रहे हों ऐसे में गलती से भी अगर वे क्यू आर कोड के सामने से निकल गए तो बिना वजह उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे । फेडरल बैंक वालों को भी पता नहीं क्या सूझा जो ये नई स्कीम उन्होंने अपने बैंक में लागू कर दी । अपने को तो डर है कि फेडरल बैंक की देखा देखी दूसरे बैंक भी इससे मिलती जुलती स्कीम लागू न कर दें इन्होंने मुस्कुराहट की बात की है हो सकता है कोई दूसरा बैंक गुस्से वाला चेहरा देखकर पेमेंट काटने लगे, कोई तीसरा बैंक ये स्कीम निकाल दे कि क्यू आर कोड के सामने जो आंख मारेगा उसका पेमेंट हो जाएगा, ना कहो कोई चौथा बैंक ये स्कीम निकाल दे कि जैसे ही आप अपनी मूंछों पर ताव दोगे आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा । कोई भोंह मटकाने पर पेमेंट कर देगा तो कोई जीभ निकाल कर चिढ़ाने पर पेमेंट की रसीद दे देगा। अपनी तो फेडरल बैंक वालों से एक ही विनती है कि भैया ऐसी उटपटांग स्कीमें मत चालू करो वरना लोग बाग मुस्कुराना भूल जाएंगे क्योंकि इधर वे मुस्कुराए और उधर उनके खाते से पैसा डेबिट हुआ । वैसे भी आजकल लोगों का मुस्कुराना कम से कम हो गया है कितनी टेंशन है जिंदगी में । घर का टेंशन, आफिस का टेंशन , महंगाई का टेंशन, बेरोजगारी का टेंशन ,सड़कों पर जाम का टेंशन, बेटी के ब्याह का टेंशन, अब जब चौतरफा टेंशन ही टेंशन हो तो आदमी मुस्कुराए कहां से यह भी तो एक सवाल है ।

चूहे मारने बिल्ली का सहारा

अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की संसद में कई फाइलें चूहों ने कतर डालीं , तमाम कोशिशें के बाद भी जब चूहों पर कंट्रोल नहीं हुआ तब सरकार ने बारह लाख रुपए की लागत से शिकारी बिल्लियां खरीदी हैं जो इन चूहों को अलसेठ देंगी। पाकिस्तान सरकार को यह बताना जरूरी है कि चूहों का आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया ,अपने भारत में ही हजारों क्विंटल अनाज चूहे खा जाते हैं दुनिया भर की दवाइयां डाली जाती है लेकिन चूहों पर उनका कोई असर नहीं होता ऐसा लगता है ये चूहे अमरौती खाकर आ आए हुए हैं वैसे ही तो पाकिस्तान में भुखमरी का आलम है उस पर बारह लाख रुपए की लागत से बिल्लियां खरीदना पड़ रही है आजकल के चूहे वैसे भी बिल्लियों को झटका देने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं । वो जमाना चला गया जब चूहे बिल्लियों के चक्कर में फंसकर अपनी जान दे देते थे । देखना होगा कि ये शिकारी बिल्लियां कितने चूहों को हजम कर पाती हैं वैसे एक बात ये भी है की हो सकता है विरोधी पक्ष के नेताओं ने फाइलें गायब कर दी हों और नाम चूहों का लगा दिया हो क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ संभव है।

इन्हें वेतन की जरूरत क्या है

हिमाचल सरकार ने अपनी डांवाडोल होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये तय किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री ,संसदीय सचिव, कैबिनेट दर्जा प्राप्त आठ सलाहकारों व सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आगामी दो महीने तक वेतन नहीं लेंगे ,मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार होगा और जब स्थिति सुधर जाएगी तो दो महीने का जो बकाया वेतन है उन्हें दे दिया जाएगा। अपना मानना तो ये है कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री इन्हें वेतन की जरूरत ही क्या है? ऐसी कौन सी फेसिलिटी है जो उन्हें मुफ्त में अवेलेबल नहीं है, सरकारी बड़ा भारी बंगला है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी पेट्रोल है, सरकारी दफ्तर है, सरकारी नौकर चाकर हैं, सब कुछ तो सरकारी है और वो भी सब फ्री मे। और जब सब कुछ फ्री में अवेलेबल है तो वेतन मिले ना मिले क्या फर्क पड़ने वाला है और फिर ये सारी चीजें तो एक नंबर में हैं दो नंबर में क्या-क्या मिलता है ये तो बच्चा-बच्चा जानता है । किसको ठेका देना है, किसका पेमेंट करना है, किसका नहीं करना है, किससे कितना कमीशन मिलना है ये सब तो आम बात है आजकल । वरना अगर सिर्फ वेतन ही के भरोसे होते नेता लोग तो मात्र पांच साल में इन नेताओं की संपत्ति पांच सौ गुना कैसे बढ़ जाती, खैर अब सरकार को समझ में आ रहा है कि वोटो के चक्कर में जो मुफ्त की घोषणाएं सरकारें कर रही हैं उसका हश्र क्या होने वाला है । अभी तो ये हिमाचल में हुआ है बहुत जल्दी अपने प्रदेश में भी यही स्थिति बनने वाली है क्योंकि जिस तरह से मुफ्त में सरकारी पैसा लुटाया जा रहा है उसकी भरपाई कहां से होगी। कितना ही गहरा कुआं क्यों ना हो लेकिन सिर्फ पानी उलीचते रहोगे तो एक न एक दिन तो वो भी खाली हो जाएगा। सरकारों को अब यह समझना होगा लेकिन अपने को मालूम है कि वोटो का चक्कर है और फिर कौन सा अपनी जेब से पैसा देना है सरकारी माल है लुटाते चलो जब खजाना खाली हो जाएगा तो आम जनता पर टैक्स का बोझ लाद देंगे जो हमेशा से होता आया है।

सुपर हिट ऑफ़ द वीक

श्रीमती जी को को उदास देखकर श्रीमान जी ने पूछा -

तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो,
गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो...?

ऐसी कोई बात नहीं है,बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई है मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो...!श्रीमती जी ने उत्तर दिया। (लेखक-चैतन्य भट्ट/ ईएमएस)

देश की आजादी में भारतवासियों का त्याग

कितने लोगों के त्याग बलिदान के पश्चात यह उपहार भारतवासियों को मिला। परंतु इस उपहार के साथ-साथ देश के विभाजन का दृश्य भी झेलना पड़ा। क्रिप्स कमीशन के आजादी घोषणा के पश्चात ही मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी। बंगाल, हैदराबाद, केरल में दंगों को देखते हुए कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत गणराज्य के बंटवारे में ही इसका हित है। हालांकि कई कांग्रेसी नेता इसके विरोध में थे। उन्हें पता था कि इस निर्णय का परिणाम अत्यंत वीभत्स होगा परंतु नियति के आगे किसकी चली है। अंग्रेजी हुकूमत ने तय किया कि भारत एवं पाकिस्तान दो देश बनाए जाएंगे तथा जो रियासत जिसमें विलय होना चाहते हैं, वे उसमें विलय हो सकते हैं। मुस्लिम बहुल रियासतों को पाकिस्तान तथा हिंदू बहुल रियासतों को भारत में रखने का निर्णय लिया गया। इस घोषणा के होते ही लोगों में होड़ लग गई अपने राष्ट्र की तरफ जाने की। सिंध, पंजाब, कराची में स्थित हिंदू, सिख भारत आना चाहते थे वहीं मध्य भारत, बंगाल, हैदराबाद, बिहार तथा देश के अन्य हिस्से के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। देश स्थानांतरण की दिशा में कई जगहों पर धार्मिक उन्माद भी उत्पन्न हो गया जिससे देश के कई स्थानों पर दंगे भड़क गए। एक आंकड़े के अनुसार 72,26,000 लोगों ने पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन किया जिसमें ज्यादातर हिंदू तथा सिख परिवार थे कई जगहों पर यह भी वर्णन है कि पाकिस्तान से आ रही सारी ट्रेनों के मुसाफिरों को मार दिया जाता था और केवल उनकी लाश ही ट्रेन में आती थी। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने परिवार बिखर गए। जनगणना के आंकड़े यह भी बताते हैं कि आजादी के पश्चात पाकिस्तान में हिंदू तथा सिख समुदाय की संख्या कुल आबादी की जनसंख्या की 22ज्ञ थी जो आज घटकर 1.6 प्रतिशत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आजादी की घोषणा होने के पश्चात जो हिंदू तथा सिख सिंध प्रांत में वर्षों से रह रहे थे, वे एकाएक बेघर हो गए। भुखमरी तथा धर्म के आधार पर लोगों ने एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दिया। यह घटना महीनों तक चली लेकिन सरदार पटेल के अथक प्रयासों के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के समय भी यही दृश्य देखने को मिला था। लेकिन हिंद के जवानों ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया तथा कश्मीर का विलय भारत में हो गया। मां भारती के सपूतों ने हर बार सिद्ध किया है कि देश के दामन पर जब-जब मुसीबतें आएंगी, वे तैयार हैं अपने भारत की रक्षा के लिए। वे न केवल भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वरन अखंड भारत के लिए भी दृढ़संकल्पवान हैं। सारांशः विभाजन एक दुखदायी स्थिति है, चाहे वह परिवार का हो या देश का। इससे देश का विकास तथा संस्कृति का क्षय होता है। (लेखक- संजय गोस्वामी/ ईएमएस)

आज का इतिहास 04 सितम्बर

1665 मुगलों और शिवाजी में पुरंधर की संधि हुई थी.
1825 दादा भाई नौरोजी का जन्म.
1887 गांधीजी कानून की शिक्षा लेने ब्रिटेन गए.
1932 फ्रांस और पोलैंड के बीच आपसी सहायता समझौता हुआ.
1959 लाओस में आपातस्थिति की घोषणा हुई.
1964 ब्रिटिश राष्ट्रकुल की फौजों ने मलाया में इंडोनेशियाई छापामारों के खिलाफ कार्यवाही शुरु की.
1975 मिस्त्र और इजरायल के प्रतिनिधियों ने जेनेवा में अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.
1987 ईरान ने इराक से युद्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्र संघ की योजना लागू करने पर सहमति व्यक्ति की.
1990 अमरीकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से मिस्र का सात अरब डॉलर का ऋण माफ करने को कहा.
1997 लेखक धर्मवीर भारती का निधन.
2001 सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सात फेरों के बिना विवाह वैध.
2005 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में 24 सुरक्षाकर्मी मारे गए.

शब्द पहेली - 8118

बाएँ से दाएँ

1.रोशनी-3
4.आशा, उम्मीद-2
5.एक प्रकार की बंगाली मिठाई-2,3
7.भ्रमण, घूमना-3
9.फिजूल, व्यर्थ ही-3
11.गुनाह, जुर्म-4
12.स्नान करवाना-4
14.डग, पांव, पैर-3
16.मक्खन(अंग्रेजी-3)
18.रावण, दशानन-5
19.टेलीफोन, दूरभाष-2
20.असली, शुद्ध-3

ऊपर से नीचे

1.वार, घात-3
2.आश्रय, पनाह-3
3.पायल की आवाज-4
4.दर्पण, शीशा-3
6.चिपकू, जलौका-2
8.स्वयं की पसंद का, स्वरुचिकर-2,3
10.हकलाना, अटक-अटक कर बोलना-5
13.पशु, जन्तु-4
14.मजार, मकबरा-2
15.कामदेव-3
16.बारिश, बरसात-3
17.धनवान, संपन्न-3

शब्द पहेली -8117 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराया, सीरीज 2-0 से जीती

रावलपिंडी (ईएमएस)। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। वहीं पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने 2-0 से सीरीज जीत ली है। ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में कोई सीरीज जीती है।

आज खेल के अंतिम दिन जीत के लिए मिले 185 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश ने चार विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की टीम ने 5वें दिन शुरुआत में दो शुरुआती विकेट लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया पर वह विफल रही। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक ने शानदार बल्लेबाजी कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। लंच तक मेहमान टीम को जीत के लिए 63 रन चाहिए थे जो उसने आसानी से बना लिए। पाक पाकिस्तान ने दूसरे सत्र में दो विकेट लिए पर मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने उसे इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया।

इससे पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद और नाहिद राणा ने पाक के 9 विकेट लिए। हसन ने 5 जबकि राणा ने 4 विकेट लिए। इससे पाक टीम दूसरी पारी में 172 रन ही बना पायी। उसके पहली पारी के आधार पर 12 रन की मामूली सी बढ़त मिली थी जिससे बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य मिला।

पाक ने पहली पारी में भी केवल 274 रन बनाए थे जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 262 रन बनाये थे।

वहीं बांग्लादेश की टीम ने पहली पारी में 26 रन पर 6 विकेट खोने के बाद लिटन दास के शतक से वापसी की। लिटन का मेहदी हसन मिराज ने भी अच्छा साथ दिया। इस प्रकार बांग्लादेश ने पहली पारी में 262 रन बनाये। लिटन दास ने 138 रन बनाए जबकि मिराज ने 78 रन की पारी खेली

बांग्लादेश के गेंदबाजों हसन महमूद और नाहिद राणा ने दूसरी पारी में भी पाक के 5 और 4 विकेट लेकर बल्लेबाजी ढ़हा दी।

अमेरिकी ओपन : स्वीयाटेक और पेगुला के बीच क्वार्टर फ़ाइनल मुकाबला

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। विश्व नंबर-1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वीयाटेक और अमेरिका की जेसिका पेगुला अमेरिकी ओपन टेनिस के महिला एकल के क्वार्टर फ़ाइनल में पहुंच गयी हैं। इगा

शेयर बाजार में सपाट कारोबार

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को मिला-जुला कारोबार हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में हल्का बदलाव हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 4.40 अंक करीब 0.01 फीसदी की हल्की मामूली गिरावट के साथ 82,555 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 1.15 अंक की हल्की बढ़त के साथ ही 25,280 पर बंद हुआ।

आज कारोबार के दौरान निफ्टी 50 के 50 में से 21 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। इनमें एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, और हीरो मोटोकॉर्प ने 1.72 फीसदी तक की बढ़त रही। वहीं दूसरी ओर, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इंफोसिस, अदानी पोर्ट्स और एचसीएलटेक के शेयरों में 1.36 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गयी।

सेंसेक्स के 12 शेयर बढ़त पर बंद हुए। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टाइटन, एचडीएफसी बैंक और नेस्ले इंडिया में बढ़त रही जबकि बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, अदाणी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचसीएलटेक के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट रही।

व्यापक बाजार सूचकांकों में बढ़त रही। वहीं बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 0.54 फीसदी की बढ़त रही, जबकि बीएसई मिडकैप 0.19 फीसदी की तेजी रही। आज कंज्यूमर डयूरेबल्स इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त रही। इसके बाद बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रहे जबकि मीडिया इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा इसके बाद मेटल, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी गिरावट रही।

इससे पहले आज सुबह एशियाई बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 50 मामूली बढ़त के साथ खुले। शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स 0.11 फीसदी की तेजी के साथ 82,652.69 पर था, जबकि निफ्टी 50 0.14 फीसदी की तेजी के साथ 25,313 पर था। हालांकि थोड़ी ही देर में शेयर बाजार ने अपनी तेजी को खो दिया और यह लाल निशान में फिसला गया। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर टॉप गेनर था जबकि बजाज फाइनेंस के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एशियाई शेयरों में नरमी देखी जा रही है। निवेशकों की नजर अमेरिका में डेटा-पैक सप्ताह पर है, जो यह निर्धारित कर सकता है कि इस महीने अपेक्षित फेडरल रिजर्व दर में कटौती नियमित होगी या सुपर-आकार की होगी।

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

- सोने के वायदा भाव 71,500 रुपए, चांदी 84,400 रुपए के करीब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने के वायदा भाव मंगलवार को तेजी के साथ खुलने के बाद सुस्त पड़ गए, जबकि चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 71,500 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 84,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में मंगलवार को सोने-चांदी के वायदा भाव तेज शुरुआत के बाद सुस्त पड़ गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रेक्ट 28 रुपये की तेजी के साथ 71,629 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 112 रुपये की गिरावट के साथ 71,489 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रेक्ट 296 रुपये की गिरावट के साथ 84,258 रुपये पर खुला। इस समय यह 160 रुपये की नरमी के साथ 84,394 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई लेकिन बाद में इनके भाव में गिरावट देखी जाने लगी। कॉमेक्स पर सोना 2,536 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,527.60 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 2.70 डॉलर की गिरावट के साथ 2,524.90 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.24 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 29.14 डॉलर था। इस समय यह 0.32 डॉलर की गिरावट के साथ 28.82 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

देश के 185 लोगों की संपत्ति जीडीपी की एक तिहाई

- मुकेश अंबानी 10.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष पर

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा 1.19 लाख करोड़ डॉलर (करीब 99.86 लाख करोड़ रुपये) हो चुकी है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सूची में 185 लोगों डॉलर अरबपति का दर्जा दिया गया है यानी उनके पास कम से कम 1 अरब डॉलर की संपत्ति है। फॉर्च्यून इंडिया वाटरफील्ड एडवाइजर्स 2024 रैंकिंग के मुताबिक भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति साल 2022 के 832 अरब डॉलर से 50 फीसदी अधिक हो चुकी है। उस समय भारत में डॉलर अरबपतियों की संख्या 142 थी। रिपोर्ट में कहा गया है ?कि यह वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और डॉलर के मुकाबले रुपये में 5 फीसदी तक की गिरावट के बावजूद संपत्ति में उल्लेखनीय इजाफे को दर्शाता है। भारत के डॉलर अरबपतियों की कुल संपत्ति अब भारत के नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 33.81 फीसदी के बराबर हो चुकी है। इस साल डॉलर अरबपतियों की सूची में रोजमर्रा के उपभोग वाली वस्तुएं (एफएमसीजी), फार्मास्युटिकल्स और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से 29 नए अरबपति शामिल हुए जिन्होंने सामूहिक रूप से 4.09 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा है कि रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी 10.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पायदान पर मौजूद हैं। उनके बाद दूसरे पायदान पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी हैं। पिछले सप्ताह हुरुन इंडिया की 2024 की सूची में अदाणी को 11.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था। इन डॉलर अरबपतियों की संपत्ति बढ़ाने में शेयर बाजार ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरबपतियों की औसत संपत्ति साल 2022 में 46,729 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर साल 2024 में 53,978 करोड़ रुपये हो गई। शीर्ष 10 डॉलर अरबपतियों की सूची में अदाणी और अंबानी के अलावा मित्त्री परिवार, शिव नादर, राधाकिशन दमानी, सुनील मित्तल और अजीम प्रेमजी मौजूद हैं। जिंदल परिवार की मुखिया एवं जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री देवी जिंदल 33.06 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष 10 की सूची में इकलौती महिला हैं और वह चौथे पायदान पर हैं।

खालिस्तानी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भारत से कनाड़ा जा रहे युवा

ओटावा (ईएमएस)।कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले लोगों में भारत से गए युवाओं की संख्या में इजाफा दिख रहा है। कई युवा तो ऐसे भी हैं, जो इन आंदोलनों में शामिल होकर सेल्फी भी लेते हैं। माना जा रहा है कि इन लोगों के प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि कनाडा सरकार ने प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐलान किए हैं। भारतीय अधिकारियों ने इसे लेकर चिंता जताई है। उन्हें संदेह है कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में खालिस्तानियों के कनाडा में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं, जो वहां बसना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि खालिस्तान की मांग वाले प्रदर्शनों में शामिल होकर वे वहां की सरकार के समक्ष माहौल बना लेंगे।

यही नहीं बीते शनिवार को भी खालिस्तानियों ने एक प्रदर्शन किया था। इस दौरान दिलावर बब्बर नाम के उस खालिस्तानी के पोस्टर लहराए गए, जो एक आत्मघाती हमलावार था। उसने पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की 29 साल पहले हत्या कर दी थी। यही नहीं ऑपरेशन ब्लूस्टार की बरसी पर इंदिरा गांधी की हत्या के चित्रण वाली तस्वीरें भी लहराई गई थीं। हालांकि अब तक यह प्रमाण नहीं मिले हैं कि इन रैलियों को आयोजित करने वालों ने ही वहां अस्थायी तौर पर बसे युवाओं को आमंत्रित किया था। हालांकि नई दिल्ली में इस बात का संदेह जताया जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि इस साल कनाडा के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब तक अधिकारियों को जानकारी मिली है कि करीब आधा दर्जन ऐसी इमिग्रेशन फर्म्स हैं, जो लोगों को सलाह दे रही हैं कि यदि वे कनाडा में रहना चाहते हैं तो खालिस्तान से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लें। इससे कनाडा की सरकार से नागरिकता के लिए दावा करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया, कुछ युवाओं को तस्वीरें लेते हुए देखा गया है। इनमें से ज्यादातर शायद नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यह एक रैकेट का हिस्सा है। इस साल खालिस्तान समर्थकों ने कई प्रदर्शन किए हैं। इन लोगों ने कई बार भारतीय कौंसुलेट्स को घेरा और राजनयिकों के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की गई। डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर जून तक 16800 लोगों ने कनाडा में रहने के लिए आवेदन किया था। यह 2023 में पूरे साल किए गए आवेदनों से भी अधिक है। इस तरह माना जा रहा है कि इस साल यह आंकड़ा कम से 25000 तक पहुंच सकता है। माना जाता है कि कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो की सत्ता आने के बाद आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। 2015 में तो यह आंकड़ा महज 380 का ही था।

भारत के मौजूदा पैरालंपिक में हुए 11 पदक

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस पैरालंपिक के तीसरे दिन भारत ने अभी तक चार मेडल अपने नाम किए हैं, जिनमें तीन मेडल बैडमिंटन में आए हैं। शटलर नितेश कुमार ने पुरुषों के मेंस सिंग्लस एसएल-3 मैच में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो वहीं तुलसीमथी मुरुगेसन को महिला एकल एसयू 5 स्वर्ण पदक मैच में चीन की किउ ज़िया यांग के खिलाफ हारकर सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। दिन का तीसरा मेडल मनीषा रामदास ने दिलाया।

मनीषा ने डेमनार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इन तीन पदकों के साथ भारत के मौजूदा पैरालंपिक में 11 पदक हो चुके हैं। उनसे पहले भारत के योगेश कथुनिया ने सोमवार को चल रहे खेलों में सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ-56 स्पर्धा में लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। बैडमिंटन स्टार सुहास यतिराज का अभी गोल्ड मेडल मैच बाकी है, जबकि स्टार तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बाद में, सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे।

बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने लगातार दो पैरालंपिक खेलों में मेडल टैली में दहाई का आंकड़ा पार किया है। भारत ने टोक्यो में 19 पदक जीते थे। पेरिस में भारत अभी तक 11 पदक जीत चुका है।

दुनिया की आधी आबादी जूझ रही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। अक्सर माना जाता है कि पोषक तत्वों की कमी गरीब देशों में ज्यादा होती है, लेकिन एक हालिया स्टडी में बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से जूझ रही है। अमीर हों या गरीब, सभी देशों में पोषक तत्वों की कमी लोगों की सेहत को बर्बाद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नई स्टडी में पता चला है कि दुनिया के 60 फीसदी से ज्यादा लोग कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और विटामिन ई समेत कई पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि यूरोपीय देशों में भी हालात बदतर मिले हैं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने 15 प्रमुख माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, थायमिन, नियासिन और विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी और विटामिन ई के अनुमानित ग्लोबल कंजप्शन का एनालिसिस किया। इसमें हैरान करने वाली बातें सामने आईं।

रिसर्चर्स ने बताया कि विश्व के 68प्रतिशत लोगों में आयोडीन की कमी, 67प्रतिशत लोगों में विटामिन-ई की कमी, 66 प्रतिशत लोगों में कैल्शियम की कमी और 65प्रतिशत लोगों में आयरन की कमी है। कैल्शियम का सेवन उत्तरी अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया में काफी कम देखने को मिला। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या को राइबोफ्लेविन, फोलेट और विटामिन सी और विटामिन बी6 भी कम मात्रा में मिल रहे हैं। नियासिन की कमी केवल 22प्रतिशत लोगों में थी, जबकि थायमिन (30 प्रतिशत) और सेलेनियम (37 प्रतिशत) लोगों में जरूरत से कम था। खास बात यह है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आयोडीन, विटामिन बी12, आयरन और सेलेनियम की कमी ज्यादा पाई गई, तो कैल्शियम, नियासिन, थायमिन, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी6 की कमी पुरुषों में ज्यादा है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से थकावट, हड्डियों में दर्द, बालों का झड़ना और कमजोरी हो सकती है।

इस रिसर्च का रिजल्ट लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश हुआ है। इस रिसर्च में शामिल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये परिणाम चिंताजनक हैं। सभी क्षेत्रों में अधिकांश लोग कई आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का सामना कर रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगे, तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।

दक्षिण अफ्रीका की ब्यूटी क्वीन बनीं मिस यूनिवर्स नाइजीरिया

- नागरिकता को लेकर आया था विवाद

एबूजा (ईएमएस)। मिस यूनिवर्स नाइजीरिया का ताज 23 साल की चिदिम्मा एडेत्शिना को पहनाया गया है जो कानून की छात्रा हैं। राष्ट्रीयता को लेकर आलोचना और विवाद के बाद उन्होंने मिस साउथ अफ्रीका प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका के सोवतो में वह पैदा हुईं। उनके पिता एक नाइजीरियाई और मां मोजाम्बिक की हैं। एडेत्शिना शुरू में मिस साउथ अफ्रीका में फाइनलिस्ट थीं। लेकिन उनकी भागीदारी की आलोचनाएं होने लगीं। आलोचकों ने उनकी मिश्रित विरासत के कारण उनकी योग्यता पर सवाल उठाए।

विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दक्षिण अफ्रीका के गृह मामलों के विभाग को जांच भी करनी पड़ गई। इस जांच में चिदिम्मा एडेत्शिना की ओर से कोई भी गलत काम करते नहीं पाया गया। लेकिन सुझाव दिया कि उनकी मां ने दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता पाने के लिए पहचान चुराई हो सकती है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आखिर में एडेत्शिना ने प्रतियोगिता से बाहर होने का फैसला किया। बाद में उनकी कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रतियोगिता से हटने की बात जानकर मिस यूनिवर्स नाइजीरिया के आयोजकों ने उन्हें अपनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। इससे उन्हें वैश्विक मंच पर अपने पिता की मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। शनिवार को लागोस में एडेत्शिना को मिस यूनिवर्स नाइजीरिया का ताज पहनाया गया। नवंबर में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगितामेंवह नाजीरिया का प्रतिनिधित्वकरेंगी। एडेत्शिना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा ?कि यह ताज सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि एकता का आह्वान है। उनकी जीत को सोशल मीडिया पर जश्न के तौर पर देखा गया। उनके समर्थकों ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन कई आलोचकों नेआरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर जीतदिलाई गई है। उनकी राष्ट्रीयता से जुड़े विवाद के कारण उनके पक्ष में धांधली की गई।

तसलीमा का दावा- बांग्लादेश में लागू हो सकता है शरिया कानून

नई दिल्ली (ईएमएस)। बांग्लादेश से निर्वासित चर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन का दावा है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ने वाला है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश में जल्द ही शरिया कानून लागू हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ शुरू हुई आंदोलन के दौरान भड़की में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल, मुल्क में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार है।नसरीन ने कहा कि अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और शरिया कानून लागू होने के बाद जल्द ही महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हालात और खराब कर देगी, क्योंकि शेख हसीना को हटाए जाने को एक जश्न की तरह मनाया गया था। अगस्त में नसरीन ने कहा था कि जिन इस्लामी ताकतों ने उन्हें बांग्लादेश से बाहर निकाला था, उन्होंने ही शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया।

तसलीमा को उनकी पुस्तक 'लज्जा' को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद 1990 के दशक में बांग्लादेश से निर्वासित कर दिया गया था। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन भड़के थे। जब नसरीन से महिलाओं की स्थिति को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं पर सबसे बुरा असर पड़ सकता है। कट्टरपंथी इस्लावादियों का बढ़ता प्रभाव महिलाओं पर पाबंदियां लगाकर उनके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और उन्हें शरिया कानून के जरिए नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालयों में लड़कियों को ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है।

जब सवाल किया गया कि क्या शेख हसीना के जाने के बाद महिलाओं के प्रति रवैये में बदलाव आया है, तो उन्होंने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब/नकाब/बुर्का को ड्रेस कोड के तौर पर लाया गया है और जल्द ही ऐसा सब सामान्य हो जाएगा।

पंजाबी गायक के घर के बाहर फायरिंग, ढिल्लो बोले-मैं सुरक्षित हूं

टोरंटो,(ईएमएस)। गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग की गई थी जिसको लेकर उनके फैंस चिंचित थे। अब सिंगर ने एक पोस्ट साझा कर कहा कि उनके कनाडा स्थित घर के बाहर गोलीबारी के बाद वह सुरक्षित हैं। पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। ढिल्लों का घर वैंकूवर के विक्टोरिया आईलैंड में स्थित है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई हैं। हमले के पीछे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया है।

इस बीच, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, हमलावरों की पहचान नहीं हो की है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने ही एपी ढिल्लों ने सलमान खान और संजय दत्त के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज़ किया था। कनाडा में हुई इस फायरिंग के बाद एक और फायरिंग की घटना सामने आई है। दूसरी घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ने ली है।

मंगोलिया पहुंचे पुतिन, आईसीसी के आदेश को दरकिनार का हुआ जोरदार स्वागत

उलनबटार,(ईएमएस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया पहुंचे गए हैं. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) ने पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए मंगोलिया को आदेश दिया था, लेकिन मंगोलिया ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। रूस के एक जानकार ने कहा कि मंगोलिया को मौजूदा समय में आईसीसी से ज्यादा रूस की जरूरत है.

मंगोलिया ने आईसीसी के आदेशों को दरकिनार करते हुए पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पुतिन के आगमन के दौरान चंगेज खान के स्मारक को दोनों देशों के झंडों से रंग दिया गया। कुछ मानवाधिकार से जुड़े लोग एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंगोलियाई सरकार की तरफ से पुतिन के स्वागत में कोई कमी नहीं की गई।

दरअसल, मंगोलिया आईसीसी का सदस्य देश है और मार्च 2023 में ही आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुतिन को यूक्रेन से बच्चों के अपहरण और युद्ध के दौरान अपराध के लिए आरोपी बताया गया है। ऐसे में आईसीसी ने पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से पुतिन अब तक12देशों की यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन वे आईसीसी सदस्य देशों से बचते रहे हैं। इन देशों में चीन, नॉर्थ कोरिया, सउदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं।

विश्व बैंक का भारत की वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान

नई दिल्ली (ईएमएस)। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग में सुधार की वजह से चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। विश्व बैंक की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। विश्व बैंक ने इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में कहा ?कि भारत जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है उसकी वृद्धि दर 2024-25 में सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है ?कि कृषि क्षेत्र में सुधार से उद्योग में आई मामूली गिरावट की आंशिक भरपाई हो जाएगी और सेवाएं मजबूत बनी रहेंगी। कृषि में अपेक्षित सुधार से ग्रामीण मांग में भी सुधार होगा।

भारत से हुए कई समझौतों को खत्म करने की तैयारी कर रही बांग्लादेश सरकार

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश में भारी हिंसा और आगजनी के बीच अंतरिम सरकार बनी है। खबरें हैं कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ऐसे समझौतों की समीक्षा की तैयारी कर रही है, जो बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं हैं। हालांकि, अब तक बांग्लादेश की ओर से ऐसे किसी एमओयू के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसके अलावा अंतरिम सरकार ने साफ किया है कि अगर कानूनी रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाना जरूरी होता है, तो प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी।

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर पूर्व में हस्ताक्षर किए हुए कुछ समझौते मुल्क के लिए गैर फायदेमंद पाए जाते हैं, तो अंतरिम सरकार उनकी समीक्षा कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर अब तक अंतरिम सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कई रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा है कि हाल ही में अंतरिम विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने हाल ही में कहा है कि एमओयू बाध्यकारी समझौते नहीं हैं और इन्हें संशोधित किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन की बैठक से लौटने के बाद हुसैन ने कहा, समझौते नहीं हैं। उनमें हमेशा संशोधन किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अंतरिम सरकार को लगता है कि शेख हसीना प्रशासन के भारत के साथ करीबी संबंध थे और हो सकता है कि एमओयू पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय हितों का खास ध्यान रखने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। जून 2024 में शेख हसीना प्रशासन ने भारत के साथ कुल 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 7 नए थे और 3 को रिन्यू किया जाना था। खबरें हैं कि बांग्लादेश को दिए जाने वाले भारतीय कर्ज को लेकर भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। प्लानिंग मंत्रालय इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट्स के जरिए जारी और प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहा है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जल संसाधन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा है कि सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऊपरी तटवर्ती और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे पर अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

ढाका में बातचीत में हसन ने भरोसा जताया कि भारत के साथ तीस्ता संधि एवं अन्य जल बंटवारा संधियों पर विवाद को बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका तो बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय वैधानिक दस्तावेजों और सिद्धांतों पर विचार कर सकता है। उन्होंने रविवार को एक साक्षात्कार में कहा, 'मैंने (बांग्लादेश में) सभी संबंधित पक्षकारों से तीस्ता जल बंटवारा मुद्दे पर चर्चा की है। चर्चा में हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि तीस्ता संधि के संबंध में हमें प्रक्रिया और संवाद को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। हमें गंगा संधि पर भी काम करना है जिसकी मियाद दो साल में पूरी होने वाली है। उन्होंने कहा, 'दोनों पक्ष सहमत हैं और तीस्ता जल-बंटवारा संधि का मसौदा तैयार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विरोध के कारण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया।

यूक्रेन के थर्माइट बम.....रुसी टैंक व गाड़ियों को सेकंड में पिघला दें

-कुछ महीनों पहले रूसी सैनिकों पर हो चुका है प्रहार

कीव,(ईएमएस)। ऊंचे-ऊंचे पेड़ों के नीचे रूसी हथियारबंद सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां छिपी हैं तभी अचानक ऊपर से एक ड्रोन आता है और पेड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आग उगलता है। ये आग सामान्य आग की तरह नहीं है. ये जहां गिर रही है, वहां चिपक जाती है। जैसे यह पिघला हुआ लावा हो। ये आग पेड़ों को जलाकर राख कर देते हैं। इसमें धमाके भी होते हैं। रूसी हथियार फटने लगते हैं। यह आग उगलने वाले ड्रोन के कई नाम है। आम बोलचाल में इसे फ्लेमथ्रोअर ड्रोन कहते हैं। फैंसी तरीके से इसे ड्रैगनफायर ड्रोन बुलाते हैं। इसके अलावा डिफेंस में इसका असली नाम थर्माइट ड्रोन है।

यूक्रेन की सेना ने अपने टेलीग्राम हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया था जिसके बाद एक्स पर हंगामा मचा गया। इस तरह का ड्रोन यूक्रेन की 108वीं सेपरेट टेरिटोरियाल डिफेंस ब्रिगेड संचालित करती है। पहले यह ड्रोन पेड़ों के नीचे छिपे दुश्मन पर आग बरसाते है, इसके बाद सारा बचा हुआ हथियार नीचे ड्रॉप कर देता है। कुछ महीनों पहले भी यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ऊपर थर्माइट बम बरसाते थे। ये बम हवा में थोड़ा ऊपर फटते थे। इसके बाद बड़े इलाके में आग लगा देते या ज्वलनशील पदार्थ छोड़ देते थे। इनका इस्तेमाल खासतौर से रूसी गाडियों को जलाने के लिए किया जा रहा था।

यह एक अत्यधिक तापमान वाला केमिकल है। इसमें जंग लगा आयरन ऑक्साइड और अल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाता है। थर्माइट का तापमान 2204 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है यानी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल जिस चीज के ऊपर किया जाएगा, वह पिघल जाएगी। यूक्रेनी सैनिक थर्माइट ग्रैनेड भी इस्तेमाल करते हैं ताकि टैंक, बख्तरबंद वाहन के जरूरी हिस्सों पर हमला करके उसे जला सकें। अगर यह ग्रैनेड टैंक के हैच के अंदर गिरा दिया जाए तो यह इतना तापमान पैदा कर देता है कि अंदर रखे गोले फटने लगते हैं। इससे टैंक में मौजूद सैनिक मारे जाते हैं. टैंक या बख्तरबंद वाहन जल जाता है।

आग उगलने वाले ड्रोन के नीचे एक या कई थर्माइट कंटेनर लगाए जाते हैं। एक कंटेनर आमतौर पर सवा दो किलोग्राम का होता है। जो करीब 22 सेकेंड तक जलता है। ये 22 सेकेंड दुश्मन के किसी भी हथियार को जलाकर खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए अगर कई कंटेनर लगे हैं तो सब आपसे में जुड़े होते हैं। एक के बाद एक जलते रहते हैं. बाद में इन कंटेनर्स को दुश्मन के ऊपर गिरा दिया जाता है।

नेतन्याहू ने जनता से क्यों माफी मांगी.....हमास से क्या कनेक्शन

येरुशलम (ईएमएस)। गाजा में मृत मिले छह इजराइली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने जनता से माफी मांगी है।

उधर हमास ने चेतावनी देकर कहा कि अगर युद्धविराम पर समझौता नहीं हुआ, तब अन्य बंधक भी 'कफन में अपने घर लौटेंगे। नेतन्याहू का यह बयान तब आया है, जब समझौता वार्ता को अंजाम देने के उनके तरीके को लेकर इजराइल में दूसरी रात भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने ये कहकर इसराइल को और हथियार देने पर रोक लगा दी है कि उनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री अब भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइली सेना का नियंत्रण जरुरी है। हमास के साथ समझौता वार्ता में यह कॉरिडोर प्रमुख मुद्दा

अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन, मांग में 10फीसदी की कमी

अहमदाबाद,3 सितंबर

अहमदाबाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़तालः राज्य स्वास्थ्य विभाग ने रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। रेजिडेंट डॉक्टर 40 फीसदी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. इस हड़ताल के कारण सिविल अस्पताल में मरीजों का नुकसान बढ़ गया है. इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों को मंगलवार (3 सितंबर, 2024) रात नौ बजे तक डयूटी पर आने या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन आज हड़ताल के दूसरे दिन डॉक्टर जुटने लगे हैं. हालांकि, आज रेजिडेंट डॉक्टर स्टाइपेंड में 30 फीसदी बढ़ोतरी की ही मांग कर रहे हैं.

अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए सिविल अस्पताल में दूसरे सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों को बुलाकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. डॉक्टर ने सोमवार (2 सितंबर) तक स्टाइपेंड में 40 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आज 40 फीसदी की जगह 30 फीसदी की मांग की गई है. यानी अब बाकी 10 टका बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी गई है. हालांकि डॉक्टरों की इस जिद के आगे सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है. रेजिडेंट डॉक्टरों से बातचीत भी टाल दी गई।

सूत्रों के अनुसार सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि मंगलवार की सुबह नौ बजे तक अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं होंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इतना ही नहीं, हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल में शामिल रहे रेजिडेंट डॉक्टरों की अनुपस्थिति भी कवर करने का निर्देश दिया है. मरीजों की कीमत पर अक्सर हड़ताल पर जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसके अलावा सरकार किसी भी कीमत पर वजीफा नहीं बढ़ाने पर आमादा है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हर तीन साल पर स्टाइपेंड में 40 फीसदी की बढ़ोतरी का कोई सरकारी संकल्प नहीं है. इसके अलावा संविदा प्रोफेसरों का वेतन 95 हजार रुपये है. जबकि रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 1.30 लाख रुपये है. सरकार किसी भी कीमत पर स्टाइपेंड बढ़ाने को तैयार नहीं है क्योंकि सिर्फ 20 फीसदी स्टाइपेंड बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 122 करोड़ रुपये का बोझ आ गया है.

मानसून के मौसम में कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, जिसके कारण अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ लग जाती है, ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, तो कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि दो दिन पहले सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों का स्टाइपेंड 20 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. हालांकि, इससे रेजिडेंट डॉक्टर नाराज हो गए और उन्होंने अपने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया।

वडोदरा में बाढ़ के बाद त्वचा रोग बढ़ेः जहरीले मलेरिया के मामले बढ़े, अकोटा में सबसे ज्यादा

वड़ोदरा.,3 सितंबर

वड़ोदरा में आंधी के कारण हर जगह पानी भर गया। विभिन्न इलाकों में जलजमाव हो गया. कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कैडेट्स के घरों में पानी भर गया। लोग पानी में रहने को मजबूर थे. अब पानी घटते ही घंटों पानी में रहने को मजबूर लोगों में चर्म रोग होने की जानकारी सामने आयी है.

वडोदरा के सयाजी अस्पताल की ओपीडी में त्वचा रोग के मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण जल जनित बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। बाढ़ के पानी में घंटों बिताने के बाद शहरवासियों को पैरों की त्वचा में खुजली, एलर्जी, जलन जैसी समस्याओं में वृद्धि देखी गई है. निगम के सूत्रों ने बताया कि हमारी ओपीडी में रोजाना करीब एक हजार से पंद्रह सौ त्वचा रोगी आते हैं। इसके साथ ही वडोदरा शहर में जहरीले मलेरिया के मामले भी बढ़ने लगे हैं. विशेषकर अकोटा क्षेत्र में विषैले मलेरिया के मरीज बड़ी संख्या में दर्ज किये जा रहे हैं. पता चला है कि मौजूदा सीजन में पिछले साल की तुलना में इस साल जहरीले मलेरिया के ज्यादा मामले सामने आए हैं.

वडोदरा में नेताओं के खिलाफ विरोध जारीः सैदीप नगर के निवासियों ने बहिष्कार के बैनर लगाए

वड़ोदरा, 3 सितंबर, 2024

व्यापक शिकायत है कि बाढ़ में लोगों की संपत्तियों को लगातार होने वाले नुकसान की पूरी जानकारी होने के बावजूद कई पार्षद अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। नागरिकों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि कई नगरसेवकों ने कई बाढ़ प्रभावित सोसायटियों का दौरा करने और वहां के नागरिकों को सांत्वना देने की भी जहमत नहीं उठाई है। आज, न्यू वीआईपी रोड पर साईदीप नगर के निवासियों ने एक बार फिर विवाद पैदा कर दिया क्योंकि उन्होंने कुछ मांगों के साथ नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए अपने दरवाजे पर बैनर लगा दिए।

वडोदरा में बाढ़ का पानी उतरे कई घंटे हो गए हैं और सफाई अभियान प्रशासन स्तर पर ही चलता नजर आ रहा है. क्योंकि जिन स्थानों पर सफाई अभियान चल रहा है, उनमें से अधिकांश स्थानों पर वे पार्षद नजर नहीं आते, जिन्हें नागरिकों ने बनाया है। क्योंकि कई जगहों पर इनका जमकर विरोध हो रहा है. कुछ नगरसेवकों ने अभी तक कई प्रभावित सोसायटियों का दौरा भी नहीं किया है। इसलिए नागरिक कह रहे हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन नगरसेवक हमारे ज्ञान के बारे में पूछने के अपने कर्तव्य से चूक गए हैं। नगरसेवक एक उपाधि है जिसका नागरिकों से सीधा संपर्क होता है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार या निगम से पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे क्षेत्र में हमारी सोसायटी में आकर स्थिति से राहत पाने की जहमत तक नहीं उठाई। फिर ऐसे पार्षदों का क्या फायदा या हमें हर बार काम कराने के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। दूसरी ओर, स्लम एरिया के कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास इलाके के सभी पार्षद ही नहीं हैं, तो एमएलए या एमपी की बात ही क्या करें? यह स्थिति दर्शाती है कि बाढ़ की स्थिति में जन प्रतिनिधियों के संपर्क से बाहर रहने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरूः जनता के सामने कौन सा रास्ता अपनाया जाए? कार्यकर्ता असमंजस में हैं

वडोदरा,3 सितंबर

बाढ़ से शहरवासियों में भारी गुस्सा है. दूसरी ओर, बीजेपी के सदस्यता अभियान ने पार्टी कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को असमंजस में डाल दिया है. क्षेत्र से जारी अधिसूचना के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे तक हर निर्वाचित जन प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी को कम से कम 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है. उन्हें आदेशानुसार क्वारंटाइन में रखा गया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल से सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया है. सदस्यता अभियान बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जितने ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे, पार्टी के लिए जीतना उतना ही आसान होगा और आने वाले महीनों में जब राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं तो पार्टी की जीत भी उतनी ही बड़ी होगी. . लेकिन वडोदरा में आई बाढ़ के कारण यहां सदस्यता अभियान पर विपरीत असर पड़ सकता है. राज्य स्तर से आग्रह किया गया है कि कल 4 सितम्बर को दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक निर्वाचित जन प्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारियों के लिए कम से कम 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है। फिर अब बाढ़ के कारण नागरिकों को किस मुंह से सदस्य बनाया जाए? वह सवाल निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए पहेली बन गया है. बाढ़ के कारण बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान कितना चुनौतीपूर्ण? अगर यह रहता है.

भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भगवा पट्टी पहनते हैं और अपने क्षेत्रों में गश्त करते हैं। तो अब वे कितने पानी में हैं? प्राथमिक सदस्य बनाने से उस बात का पता चल जायेगा. फिलहाल जब बाढ़ की स्थिति है तो नागरिकों में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है. ऐसे में मजदूरों के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है.

एक ओर जहां बाढ़ के कारण वडोदरा में सदस्यता अभियान को बड़ा झटका लग रहा है. उधर, चर्चा है कि सदस्यता अभियान को लेकर निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच अलग-अलग राय सामने आयी है. ऐसा लगता है कि बीजेपी सदस्य बनाने की जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता तलाश रही है! क्योंकि इस मामले में भी दोनों के बीच मनमुटाव की बातें सतह पर आ गई हैं. पार्टी के एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वैसे तो हम निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं, लेकिन पार्टी में किसे शामिल करना चाहिए और किसे नहीं? यह पार्टी का मामला है. इसलिए पार्टी कार्यकर्ता इसमें भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर, संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे एक व्यक्ति ने कहा, अगर सदस्यता अभियान ही संगठन की जिम्मेदारी है, तो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अपने कर्तव्य के लिए क्या बचा है? इस प्रकार, भाजपा पार्टी के लिए सदस्यता अभियान का मुद्दा पार्टी के पदाधिकारियों और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के बीच एक आंतरिक शीत युद्ध का मुद्दा बनने की संभावना है।

आम आदमी पार्टी अब एक टूटी हुई पार्टी बन गई हैः कुमार कनानी

सूरत,3 सितंबर

सूरत में पैन पार्क के ठेकेदार से 11 लाख की रिश्वत मांगने के मामले में विपक्षी पार्षद की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी एक टूटी हुई पार्टी बन गयी है.

ठेकेदार ने सूरत नगर निगम के विपक्षी नगरसेवक विपुल सुहाग्य और जीतेंद्र काचड़िया के खिलाफ 11 लाख की रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के सबूत मिलने के बाद एसीबी ने एक पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य पार्षद के खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी. इस गिरफ्तारी के बाद वराछा विधायक कुमार कनानी सामने आए हैं और आम आदमी पार्टी को टूटी हुई पार्टी बता रहे हैं. कुमार कनानी ने कहा कि इस पार्षद द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बिल्कुल स्वाभाविक है. क्योंकि अब आम आदमी पार्टी एक टूटी हुई पार्टी बन चुकी है, उसके मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल हों या मनीष सिसौदिया या अन्य सभी विधायक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं. फिर यहां उनके पार्षद का भ्रष्टाचार करना स्वाभाविक है। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी है, ईमानदार पार्टी के रूप में लोगों ने उन पर भरोसा किया. उस भरोसे को तोड़ कर यह पार्टी अब भ्रष्टाचार में डूब गयी है. कुमार कनानी के आरोप के बाद सूरत की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है.

10 लाख की रिश्वत के मामले में आप का एक पार्षद गिरफ्तार

सूरत (ईएमएस) कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के दो नगर पार्षदों के खिलाफ सूरत में 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला दर्ज हुआ हैं इस मामले में एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने आप के एक नगर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया हैं जबकि फरार दूसरे नगर पार्षद की सरगर्मी से तलाश कर रही हैं जानकारी के मुताबिक सूरत में आप के दो नगर पार्षदों के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया हैं पार्षद विपुल सुहागिया और जितेंद्र काछडिया के खिलाफ 10 लाख की रिश्वत मांगने अपराध दर्ज किया गया हैं आप के नगर पार्षदों पर आरोप है कि दोनों ने एक कोन्ट्रेक्टर से रु. 10 लाख बतौर रिश्वत मांगी थीं साथ ही कोन्ट्रेक्टर को धमकी दी थी कि अगर रु.10 लाख नहीं दिए तो वह उसका कोन्ट्रेक्ट रद्द करवा देंगें रिश्वत मांगने वाले दोनों नगर पार्षदों के ऑडियो कोजांच के लिए एफएसएल को भेजा गया और आखिरकार ऑडियो उन्हीं का साबित हुआ। जिसके बाद पार्षद विपुल सुहागिया को गिरफ्तार कर लिया गया है

आत्मनिर्भर महिलाओं ने पिछले साल सूरत के माटी मूर्ति मेले में एक करोड़ की मूर्तियां बेचीं

सूरत,3 सितंबर

सूरत गणपति विशेषः सूरत में महिला कारीगरों को गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान में, पिछले साल सूरत शहर में 49 संगठनों ने एक करोड़ से अधिक मूर्तियां बेचीं।

इससे पहले, सरकार ने राज्य के कारीगरों को मिट्टी से इको-फ्रेंडली मूर्तियां बनाने के लिए तैयार करने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान और राज्य के 65 विशेषज्ञ कारीगरों को प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया था और उन्हें मिट्टी की मूर्तियां बनाने और उन्हें बेचने के लिए प्रशिक्षित भी किया था।

सूरत में 1 सितंबर से गणेश चतुर्थी तक गंगेश्वर महादेव मंदिर स्थित म्यूनिसिपल मल्टीपर्पज हॉल में माटी मूर्ति मेला का आयोजन किया गया है. आत्मनिर्भर महिलाएं और उनके संगठन शहर में मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बेचने लगे हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा प्रवर्तित ठवोकल फॉर लोकलठ पहल की भावना में, गुजरात पॉटरी कारीगर और ग्राम प्रौद्योगिकी संस्थान कारीगरों की आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 से महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। . जिसमें गणेश प्रतिमा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ ही प्रचार-प्रसार एवं बिक्री का अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

सूरत समेत राज्य के अन्य शहरों में गणपति उत्सव से पहले माटी मूर्ति मेले का भी आयोजन किया जाता है. पिछले साल सूरत के इस मेले में 40 से अधिक महिला संगठनों और मूर्ति बनाने वाली 9 महिलाओं ने एक करोड़ रुपये से अधिक की श्रीजी की मूर्तियाँ बेचीं।

8वीं कक्षा की छात्रा से शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोप में आश्रम शाला का प्रिंसिपल गिरफ्तार

नवसारी (ईएमएस) राज्य में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई हैं नवसारी जिले के दूरदराज क्षेत्र की आश्रम शाला के आचार्य ने 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ कीं छात्रा के अभिभावक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आश्रम शाला के आचार्य को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की हैं बता दें कि हाल ही में खेडा जिले के कठलाल से भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थीं जिसमें विधर्मी शिक्षक ने 4थी कक्षा की छात्रा के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की थीं इस मामले में कठलाल पुलिस विधर्मी शिक्षक को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही हैं ताजा घटना दक्षिण गुजरात के नवसारी जिले की हैं आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को उचित शिक्षा मिले इसके लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं। जिसमें दूरदराज के इलाकों में आश्रमशालाएं बनाई गई हैं ताकि बच्चे वहां रहकर पढ़ाई कर सकें नवसारी जिले की वांसदा तहसील के भीतरी इलाके में स्थित वाल्मिकी आश्रमशाला में रहने वाले भूपेश अमृत वहिया 15 वर्षों से आश्रम स्कूल में शिक्षक और प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है। एक बेटी का पिता भूपेश वहिया कुछ समय से आश्रम शाला में पिछले 5 सालों से पढ़ रही छात्रा गंदी नजर से देख रहा थ कि कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा को प्रिंसिपल के गंदे के इरादों से अंजान थीं भूपेश वहिया कभी कविता सिखाने अपने कार्यालय में तो कभी छात्रा के कमरे में पहुंच जाता और उसके साथ शारीरिक छेड़छेड़ करतं हांलाकि इस प्रकार शिक्षक द्वारा शरीर को छूना छात्रा को अजीब लग रहा थं लेकिन मासूम छात्रा को पहले तो शिक्षक का व्यवहार समझ नहीं आयं गत 24, 25 और 28 अगस्त को जब इस मनचले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं इस घटना के बाद छात्रा ने शिक्षक द्वारा उसके साथ हुए अभद्र व्यवहार के बारे में अपने परिवार को बतायां जिसके बाद परिवार ने वांसदा थाने में शिकायत दर्ज कराईं पुलिस ने कुछ ही घंटों में मनचले आचार्य को गिरफ्तार कर लिया और उसका मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी हैं क्या आचार्य भूपेश ने अन्य छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उनके साथ छेड़छाड़ की है? पुलिस ने उस दिशा में जांच शुरू कर दी हैं इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हैं

कोस्ट गार्ड का हेलिकॉप्टर समुद्र में गिरा

अहमदाबाद(ईएमएस)। गुजरात के पोरबंदर तट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर (ध्रुव) अरब सागर में गिर गया। हेलिकॉप्टर पर सवार 4 में से 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं। एक को बचाया गया है। हेलिकॉप्टर का मलबा मिल गया है। अधिकारियों ने बताया कि हेलिकॉप्टर पोरबंदर तट से 45 किलोमीटर दूर कार्गो शिप पर रेस्क्यू मिशन के लिए गया था। हेलिकॉप्टर पर 2 पायलट और 2 गोताखोर सवार थे।

6 सितंबर को सूरत से जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ होगा

गांधीनगर (ईएमएस) केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय एवं गुजरात सरकार के संयुक्त उपक्रम से 6 सितंबर को सूरत से जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वर्चुअली उपस्थित रह कर मार्गदर्शन देने वाले हैं, जबकि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल एवं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश के राज्यों में जल संचय संबंधी कार्यों के लिए 'कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स-व्हेन इट फॉल्स' थीम के साथ वर्ष 2021 से जल शक्ति अभियान चलाया जाता है।वर्ष 2024 में 'नारी शक्ति से जल शक्ति' थीम के साथ 9 मार्च से 30 नवंबर, 2024 तक जल शक्ति अभियान आयोजित हो रहा है।

तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे निरस्त

परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं के कारण पश्चिम रेलवे द्वारा 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निरस्त की जाने वाली ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

निरस्त की जाने वाली ट्रेनें

7 और 14 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल – कटिहार साप्ताहिक स्पेशल

10 और 17 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09190 कटिहार – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल

11 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक स्पेशल

12 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल

15 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल – कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक स्पेशल

16 सितंबर, 2024 की ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज – मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल

सूरत शिक्षा समिति तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाएगी

सूरत ,3 सितंबर,

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गुजराती बच्चों का यह मिथक अब टूटने वाला है कि उनकी अंग्रेजी बहुत कच्ची है और वे पढ़-लिख नहीं सकते। देश के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान देने के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने पूरे गुजरात में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के लिए सूरत शिक्षा समिति स्कूल का चयन किया है। आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कुछ ही समय में समिति विद्यालय के कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करेगी।

सूरत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के कुछ छात्र पूरे गुजरात में अग्रणी हैं जबकि कुछ छात्र कच्चे हैं। ऐसे समय में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में पांच लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी का पाठ पढ़ाने वाली स्टेप अप फॉर इंडिया साथ दो नामक संस्था ने गुजरात में इस ऑपरेशन के लिए सूरत को चुना है। कंपनी फंड प्रोजेक्ट के तहत सूरत नगर पालिका के कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को स्पोकन इंग्लिश, व्याकरण सहित शिक्षा प्रदान करेगी।

एनजीओ सूरत समिति के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा और इसके लिए फंड खोजने का काम एनजीओ द्वारा किया जाएगा। द्वारा किया जाएगा इस संबंध में आज होने वाली आम बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही समिति स्कूल के कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी.

अन्य राज्यों में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन ने गुजरात में इस परियोजना के लिए सूरत नगर पालिका द्वारा संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति स्कूल का चयन किया है।

पहले चरण में सूरत नगर निगम संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के कक्षा3से5तकके6हजार विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही एन.जी.ओ कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ-साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। अगर इन शिक्षकों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो भविष्य में समिति स्कूल में छात्र भी सख्ती से अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे।

वडोदरा में भारी बारिश के कारण साधली से सेगवा मार्ग बंद

वड़ोदरा, 3 सितंबर,

साधली से सेगवा मार्ग अवाखाल के पास ओवरटॉपिंग के कारण बंद हो गया है। पिछले सप्ताह वडोदरा जिले में भारी बारिश के कारण कई सड़कें प्रभावित हुईं। जिसे युद्ध स्तर पर फिर से शुरू कर दिया गया है.

आज साधली से सेगावा को जोड़ने वाला राज्य राजमार्ग अवाखाल गांव केपास एक से दो फीट पानी केकारणबह रहा है। इसलिए यह रास्ता बंद कर दिया गया है. सुरक्षा और एहतियात के तौर पर एक बाढ़ गेज भी स्थापित किया गया है। वैकल्पिक मार्गके रूप में साधली से कायवरोहण से दभोई से सेगवा तक जा सकते हैं। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता यूसी पटेल ने कहा.

पश्चिम रेलवे द्वारा 6 जोड़ी गणपति स्पेशल

गणपति महोत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा वाया वसई रोड, पनवेल और रोहा स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के 56 फेरों का परिचालन किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गणपति स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1.ट्रेन संख्या 09001/09002 मुंबई सेंट्रल –ठोकुर साप्ताहिक स्पेशल (06 फेरे)2.ट्रेन संख्या 09009/09010 मुंबई –सावंतवाड़ी रोड स्पेशल (26 फेरे) (मंगलवार/बुधवार को छोड़कर)

3.ट्रेन संख्या 09015/09016 बांद्रा टर्मिनस – कुडाल साप्ताहिक स्पेशल (06फेरे)4.ट्रेन संख्या09412/09411 अहमदाबाद–कुडाल साप्ताहिक स्पेशल (06 फेरे)

5.ट्रेनसंख्या09150/09149 विश्वा मित्री–कुडाल साप्ताहिक स्पेशल (06 फेरे) 6. ट्रेन संख्या 09424/09423 अहमदाबाद–मंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल (06 फेरे)

ट्रेनों के समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया ''.हिन्दि.ग्र्ह्रीहैंग्तुदन्ग्ह पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पार्कसंस कार्टामुंडी ने गुजरात में प्रतिष्ठित साइकिलएँ ब्रांड प्लेइंग कार्ड पेश किया

ताश के पत्तों के अग्रणी वैश्विक ब्रांड पार्कसंस कार्टामुंडी ने भारत में आइकॉनिक साइकिलएँ ब्रांड पेश किया है। यह रणनीतिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि प्रतिष्ठित अमेरिकी ब्रांड गुजरात के कार्ड उत्साही लोगों के साथ शुरुआत करते हुए स्वर्णिम भारतीय बाजार में शानदार प्रवेश कर रहा है। इस कदम के बारे में बोलते हुए, पार्कसंस कार्तमुंडी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और एमडी, श्री कपिल केजरीवाल ने कहा, ''हम भारतीय बाजार में विशेष रूप से स्वर्णिम राज्य गुजरात में एक प्रसिद्ध साइकिल ब्रांड लाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। ताश के खेल के प्रति गहरे प्रेम वाले इस प्रतिष्ठित ब्रांड के लिए गुजरात एक आदर्श बाजार उपलब्ध कराता है, विशेष रूप से जन्माष्टमी जैसे उत्सव के अवसरों के दौरान। कार्ड गेम हमेशा से ही इस उत्सवपूर्ण पारिवारिक समारोह का एक मज़ेदार हिस्सा रहा है। कार्टामुंडा के ग्रुप सीईओ स्टीफन मर्कक्स ने कहा, ''हम भारतीय उपभोक्ताओं के लिए साइकिलएँ ब्रांड पेश करने और उन्हें एक अद्वितीय खेल अनुभव प्रदान करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। खेल के प्रति भारत का गहरा लगाव और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे हमारे लिए साइकिलएँ के जादू को साझा करने का एक आदर्श मंच बनाती है। गुणवत्ता और नवाचार के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भारतीय उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं के साथ पूरी तरह मेल खाती है। यह साझेदारी कार्ड गेम के समकालीन आनंद को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर हमारी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करती है। पार्कसंस कार्टामुंडी और साइकिलएँ के बीच गठजोड़ परंपरा, गुणवत्ता और नवीनता को जोड़ने वाले उत्पाद के साथ भारतीय बाजार को लुभाने की हमारी रोमांचक यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।

रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च की2024क्लासिक 350

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, अपनी सदाबहार खूबसूरती, पुराने जमाने के आकर्षण, और मजबूत स्वभाव के साथ, 2008 में लॉन्च होने के बाद से शानदार ऑटोमोटिव डिजाइन, खूबसूरती और इंजीनियरिंग का प्रतीक रही है। इस मोटरसाइकल में हमेशा रॉयल एनफील्ड की असली पहचान बनी रही है। आज इसी मोटरसाइकिल का नया रूप, 2024 क्लासिक 350, लॉन्च किया गया है। 2024क्लासिक 350 में रॉयल एनफील्ड केसभीखासगुणबरकरार हैं,रॉयल एनफील्ड के सीईओ,बीगोविंदराजन ने 2024क्लासिक 350के बारे में कहा, ठक्लासिक350,रॉयल एनफील्ड की असली मोटरसाइकिल पहचान का सही रूप है। यह मोटरसाइकिल अपनी खूबसूरती, शानदार कारीगरी, और सदाबहार स्टाइल के लिए जानी जाती है। सालों बाद भी इसका आकर्षण और खासियत जस का तस बना हुआ है, और यह लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। साथ ही, इसमें कस्टमाइजेशन की भी कई संभावनाएं हैं। हम इन सभी खूबियों को बरकरार रखते हुए क्लासिक 350को नए फीचर्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं। हमें खुशी है कि शुरुआती बुकिंग करने वाले कुछ ग्राहकों को रॉयल एनफील्ड फैक्ट्री कस्टम प्रोग्राम के तहत अपनी पसंद की मोटरसाइकिलबनानेकामौकादेंगे। तिरुवोट्टियूर का हमारा कारखाना हमारे लिए बहुत खास है, और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब यहाँ इस खास कस्टम प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा।

एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफ़र लॉन्च किया ; 5 सितंबर को खुलेगा एनएफओ

मुम्बई : एचएसबीसी म्यूचुअल फंड ने एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट ऑपर्च्युनिटीज फंड को लॉन्च करने की घोषणा की, जो निर्यात विषय के तहत एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना है। नया फंड ऑफर (एनएफओ) 05 सितंबर 2024 को खुलेगा और 19 सितंबर 2024 को बंद होगा ।

एचएसबीसी इंडिया एक्सपोर्ट ऑपर्चुनिटीज़ फंड (योजना) का लक्ष्य वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात से जुड़ी या उससे लाभान्वित होने वाली कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों के सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो से लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि उत्पन्न करना है। इस योजना में उन कंपनियों में निवेश करने की सुविधा है जो बाजार पूंजीकरण में निर्यात विषय का हिस्सा हैं जैसे कि- लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। यह योजना निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) को ट्रैक करेगी।

इस योजना का प्